देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 13.03.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई।
- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा – घरेलू एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
- एलपीजी और ईंधन की कालाबाजारी पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रदेशभर में व्यापक जांच अभियान जारी। पिछले तीन दिनों में 280 निरीक्षण किए गए।
- राज्य में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 'प्ली बार्गेनिंग' प्रावधानों के व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश।

प्रधानमंत्री / चिंता

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की मृत्यु और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादों व ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने का आग्रह किया।

प्राकृतिक गैस मंत्री

केंद्र सरकार ने संसद में आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है और घरेलू एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग से डिलीवरी तक के ढाई दिन के वर्तमान समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्री पुरी ने कल लोकसभा में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने पर सरकार के कदमों के बारे में बयान दिया।

पीआईबी

पत्र सूचना कार्यालय– पीआईबी के नेतृत्व में ओडिशा से आए वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने टिहरी बांध के पावर हाउस और टिहरी झील का भ्रमण किया। दल का नेतृत्व कर रहे पीआईबी के सहायक निदेशक महेंद्र जैना ने बताया कि टिहरी बांध की झील पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। उन्होंने कहा कि भ्रमण का उद्देश्य ओडिशा में इस झील का प्रचार–प्रसार करना है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ सकें। श्री जैना ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने यहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को देखा और समझा।

जयंती पार्क

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ के नेडा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रजत जयंती पार्क को मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने बताया कि लगभग 58 नाली भूमि पर बनने वाले इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। इसमें वॉटर फाउंटेन, ओपन थियेटर, चिल्ड्रन पार्क और कैफेटेरिया सहित विभिन्न मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि यह पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा पार्क होगा।

ईंधन / निरीक्षण

राज्य में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश भर में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय आयुक्त ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 280 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 58 स्थानों पर छापे मारे गए। साथ ही चार प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। अभियान के दौरान अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्रवाई के दौरान वजन माप उपकरण और रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं। विभाग ने अनियमितताओं पर अर्थदंड भी वसूला गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस व ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध रिफिलिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि एलपीजी या ईंधन से संबंधित अनियमितता, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त ने कहा कि विभाग की ओर से आगे भी इसी प्रकार सघन जांच अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।

प्ली बार्गेनिंग

प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव गजेन्द्र सिंह कफलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के तहत 'प्ली बार्गेनिंग' के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार के राज्य के संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने विभागों को प्रेषित पत्र में कहा है कि न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने और अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसलिए जनहित में इसके प्रावधानों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जानी आवश्यक है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किए गए नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और अदालतों पर लंबित मामलों के दबाव को कम करना है। इसके तहत सात वर्ष से कम कारावास की सजा वाले मामलों में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आरोपी को 'प्ली बार्गेनिंग' के लिए आवेदन करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

औचक निरीक्षण बागेश्वर

बागेश्वर जिला प्रशासन की टीम ने बागेश्वर स्थित नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, उपचार सेवाओं और औषधियों के रखरखाव की गहन जांच की गई। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने औषधियों के रख–रखाव, क्रय बिलों और औषधि रजिस्टरों की प्रविष्टियों की बारीकी से जांच की और यह सुनिश्चित किया कि सभी औषधियां सुरक्षित तरीके से और निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी गई हैं।

टीम ने केंद्र में उपचार ले रहे मरीजों से भी बातचीत की। मरीजों से उनके अनुभव और केंद्र में मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। साथ ही स्टाफ को नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपचार सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।